LOK SABHA

Wednesday, March 14, 1984
Phalguna 24, 1905 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Study made with regard to Socio-Economic Developments of Scheduled Castes in Rural Areas

*243. SHRI MANI RAM BAGRI :
SHRI TRILOK CHAND :
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any study has been made by Government to know the socio-economic development of Scheduled Castes in the rural areas of the country particularly in Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Orissa and Haryana;

(b) if so, the details thereof stating the percentage of Scheduled Castes households living in absolute poverty and proportion of the community living below poverty line; and

(c) the steps taken by Government to improve their socio-economic conditions ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सामान्य रूप से यह मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों की बड़ी संख्या आर्थिक रूप से अत्यधिक वंचित है। राज्यों ने छठी योजना में बनाई गई संघटक योजना की नीति अपनाई है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अनुपात तथा संख्या का अनुमान लगाया है। अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों की समस्त जनसंख्या को गरीबी की रेखा से नीचे माना गया है।

इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के कुछ खण्डों में एक अध्ययन अयोजित किया गया है और रिपोर्ट के प्रारूप की जांच की जा रही है।

(ग) राज्यों में, उनकी विशेष संघटक योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष विभिन्न विकास कार्यक्रम तैयार तथा क्रियान्वित किये जाते हैं। इस प्रयास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बिशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, असल में यह जवाब गोल मटोल दिया है क्योंकि इसमें कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं, कोई बुनियादी जवाब नहीं है, गरीबी की रेखा से कितने नीचे हैं, क्या रेखा है यह कुछ नहीं बताया गया। जो 3 आने, 15 आने वाली डा० लोहिया की बहस चली थी उस वक्त भाव क्या थे और आज क्या हैं, कितनी खुराक कम से कम एक प्राणी को मिलनी चाहिए गांव के और शहर के, जैसे आप हैं मंत्री और दूसरा हो संतरी या गांव में काम करने वाला उसकी खुराक और आमदनी क्या हो इसका कुछ पता नहीं। आमदनी उसकी ज्यादा जो कम काम करे और खुराक की जरूरत उसको जो ज्यादा काम करे इन अन्तरों को, बुनियादी सवालों को...

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Sir, something more was to be added to my original reply.

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सोच रहा था कि

अगर श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने आंकड़े देने शुरू कर दिये तो सारा सवाल हो जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जंजाल को साफ करना चाहता हूं कि पर-कैपिटा का मतलब क्या है? बिरला की आमदनी और एक अति गरीब की आमदनी, दोनों पर-कैपिटा में बराबर आती हैं। खेत पर काम करने वाले की आमदनी और मैनेजर या आपके चैयरमैन की आमदनी पर-कैपिटा में बराबर आती हैं। दोनों उसमें शामिल होती हैं। जिसको 49 परसेंट या 48 परसेंट भोजन मिले उसे भी और जिसे 2 परसेंट भोजन मिले उसे भी आप एक ही श्रेणी में लेते हो। मैं जानना चाहता हूं कि बिलो पावर्टी का आपका पैमाना क्या है और कम-से-कम आमदनी, अति-कम आमदनी वाले का पैमाना क्या है? उनकी तादाद किस हिसाब से है?

गृह मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक गरीबी की रेखा का सवाल है, यह मूल उत्तर में बताया गया है कि जितने भी हरिजन हैं, करीब-करीब सभी गरीबी की रेखा के नीचे माने गये हैं, लेकिन प्रयास यह है कि 50 प्रतिशत से ऊपर लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाये। जहां तक डा० लोहिया के टाइम के आंकड़े हैं और अब के आंकड़े हैं, उनमें बहुत अन्तर आ गया है, तीन आने वाला सवाल अब नहीं है। अधिकतर हरिजन गांव में मजदूरी का काम करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने यहां मजदूरी नियत की हुई है, कहीं वह 6 रुपये है, कहीं 8 रुपये है और कहीं 11 रुपये भी। है मैं यह बात स्वीकार करता कि इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और अधिकांश लोगों को यह तनख्वाएं मिलती नहीं हैं, इसलिए उनकी हालत अभी भी खराब है। इसलिए छठी प्लान में इसमें 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाये और इनको ग्रमीण धन्धे दिलवाने का प्रयास किया जाये।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप समझते हैं कि मेरे सवाल का जवाब आ गया?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप समझ गये हों तो समझ जाऊं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं तो बाद में समझूंगा।

इसी अधार पर एक सवाल और करना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने 4800 करोड़ रुपये की बात कही, क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पैसा इमदाद के लिये लगाते हैं उसमें 100 रुपये में से कितना रुपया मशीनों, मशीनों की सुविधा, नौकरशाह, उसका दफ्तर, मोटर गाड़ी, तेल-भत्ता, बीच के दलाल और रिश्वत पर खर्च होता है और कितना सही आदमी तक पहुंचता है? क्या कभी आपने इसका हिसाब लगाया है कि कितना उस आर्गेनाइजेशन पर खर्च होता है जिसके जरिये आप इस राशि का बंटवारा करना चाहते हैं और कितना उनको मिलता है जिसके लिए आप खर्च करना चाहते हैं? क्या कभी इसका विश्लेषण किया गया है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है यह तो प्रत्येक राज्य सरकार देखती है। यह जो आंकड़े दिये हैं यह राशि तो खासतौर पर उन पर खर्च की जाती है जिनको इसकी जरूरत है। यह नहीं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मोटर-गाड़ी का भत्ता वगैरह सब शामिल हैं। यह उन लोगों को ऊपर उठाने के लिये खर्च की जाती है जो

गरीबी की रेखा के नीचे हैं । मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चहता हूं कि 1982 83 में इस पर 675.76 करोड़ रुपये खर्च किया गया और 1983-84 में उसको बढ़ाकर 754.86 करोड़ कर दिया गया और अब 1984-85 में यह रकम और बढ़ाई जा रही है इसलिये यह रकम तो वही बताई है जो मूलत: उन पर खर्च की जाती है ।

श्री मनीराम बागड़ी : सरकार ने अनुसूचित जातियों के सब व्यक्तियों को बिलो पावर्टी लाइन माना है और यह भी बताया है कि उन पर इतना पैसा खर्च किया गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने किसको पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारा लक्ष्य 50 परसेंट लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का है और यह लक्ष्य छठी पंच-वर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ।

श्री त्रिलोक चन्द : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि सदन को गुमराह किया गया है । सवाल में साफ तौर से पूछा गया है कि क्या सरकार ने अध्ययन कराया है या नहीं । सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है । पहले मंत्री महोदय बताएं कि अध्ययन हुआ है या नहीं, उसके बाद मैं सप्लीमेंटरी पूछूंगा ।

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : A study on the socio-economic development of scheduled castes and scheduled tribes was sponsored by the Ministry of Home Affairs and was undertaken by the Giri Institute of Development Studies, Lucknow.

इस इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश में उत्तर काशी, सहारनपुर, जालोन, सीतापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित पांच ब्लाक्स का सरवे किया है ।

श्री त्रिलोक चन्द : लखनऊ के जिस इंस्टीट्यूट ने पांच ब्लाक्स की स्टडी की है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिलो पावर्टी लाइन के शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या में डिक्लाइन हुआ है, पहले वे 84 परसेंट थे और अब 80 परसेंट हो गए हैं, 4 परसेंट की कमी हुई है । उसमें लिखा है कि अगर इसी रैशो से गरीबी हटी तो गरीबी को हटाने में दो सौ साल लगेंगे, उससे पहले नहीं । इस इंस्टीट्यूट ने पांच ब्लाक्स की स्टडी की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने कोई एनक्वारी कराई है या नहीं । छ: पंच-वर्षीय योजनाएं बीत जाने पर भी मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह गए हैं । सरकार ने अध्ययन नहीं किया है । मंत्री महोदय ने सामान्य रूप से कहा है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा । जहां तक अध्ययन का सवाल है, प्रत्येक राज्य सरकार को कहा गया है कि वह अध्ययन कराए । जिन स्टेट्स में हरिजनों की संख्या अधिक है, उन सब ने अध्ययन किया है । इसके अलावा जो रिपोर्ट है, उसके 18 वाल्यूम्ज होम मिनिस्ट्री में आए हैं, जिनका एग्जामिनेशन हो रहा है । माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं मालूम होता है कि पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में कोई गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा है ।

The study is confined to five blocks of UP and its findings are under examination of the Ministry of Home Affairs.

SHRI ARVIND NETAM : I would like to know whether the Government is

satisfied with the implementation of the Special Component Plan programme in the various States. If not, what steps is the Government going to take in this regard ?

SHRI P C. SETHI : We are certainly not satisfied with the implementation of the programme and that is why we have been sending survey teams of officers; we have also established a monitoring team which goes to the various States and monitors the programme. Certainly the programme needs to be implemented in its right earnest, which is not being done at present.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को चैलेंज करता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में 50 परसेंट लोग, खासकर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएंगे । पता नहीं, माननीय मंत्री ने कहां के आंकड़े लिए हैं और किन आंकड़ों के तहत वह जवाब दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि गरीबी बढ़ती जा रही है । मैं इतने ज्यादा सवाल पर नहीं जाऊंगा । मैं मंत्री महोदय से इतना ही कहूंगा कि जैसे कोई होशियार चोर चोरी करने के लिए चलता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लेता है और ज्यों ही कुत्ते की आवाज आई, रोटी का टुकड़ा फेंक देता है, चोर चोरी करने में मस्त है और कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाने में मस्त हो गया, इसी तरह की सरकार की नीति है । हमारे पास में यह रिकार्ड एंड कैरियर्स है, इन्होंने हरिजन और आदिवासियों के लिए 44 संस्थाओं का नाम गिनाया है कि इतनी संस्थाएं जो इनके लिए काम कर रही हैं उसमें से हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली और हरिजन सेवक संघ हावड़ा भी है । जो इसका अनुदान है वह एक एक साल में आप देखें, 1980-81 में एक जगह पर 13 लाख, दूसरे साल में 18 लाख, तीसरे साल में 19 लाख इस तरह का चल रहा है । लेकिन आज तक शेड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर होने के नाते स्वयं हमको नहीं मालूम है कि इनका क्या काम है । इनकी अध्यक्ष निर्मला देशपांडे जी हैं । इसी तरह की और भी संस्थाएं हैं, हरिजन सेवक संघ है, और और भी कई संस्थाएं हैं । हमको यह पता नहीं चलता कि इनका काम क्या है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो हरिजन और आदिवासियों के नाम पर इतनी संस्थाएं चला रखी हैं और गवर्नमेंट अनुदान दे रही हैं इनको, इन संस्थाओं का काम क्या है ?

दूसरी बात, मैंने 1980 में इसी सदन में पूछा था कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप इतना फंड्स देते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए देते हैं, तो क्या होम मिनिस्ट्री के अंडर में एक अलग डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए खोलेंगे ? सरकार ने कहा कि यह ऐक्टिव कंसिडरेशन में है । अब तक चार साल हो गए, चुनाव का समय आने वाला है, उस ऐक्टिव कंसिडरेशन का क्या हुआ ? होम मिनिस्ट्री के अंडर में अलग डिपार्टमेंट खोलने का निर्णय आपने लिया है या नहीं लिया है और ये जो इतनी संस्थाएं है इन के ऊपर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वह क्या काम कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है, यह हरिजनों के लिए स्कूल और होस्टल्स चलाती हैं, उस के लिए दिया जाता है ।

श्री राम विलास पासवान : कहां चलाती हैं ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : चलाती हैं ।

श्री राम विलास पासवान : कहां चलाती हैं ? एक जगह का नाम बतलाइए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : राम दुलारी जी कह रही हैं इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि चलाती हैं।

जहां तक सेपरेट डिपार्टमेंट खोलने का सवाल है, यह मैंने जरूर यहां पर कहा था कि यह मामला विचाराधीन है । मैं माननीय सदस्य को फिर यह कहना चाहूंगा अनुरोध-पूर्वक कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

श्री राम विलास पासवान : यह क्या जवाब हुआ ? एक स्कूल का नाम नहीं लिया और विचाराधीन अभी भी है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका ऐसा कर सकते हैं कि जितने स्कूल हैं वह सारा आपको भेज दें और इसके ऊपर फिर डिस्कशन हो जाय।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : They have to be more responsible in answering questions they appear to be very serious about it.

MR. SPEAKER : They are more serious.

श्री मनीराम बागड़ी : आप इसको 193 के अन्दर बहस में लीजिए... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस करवा दीजिए...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : No, Sir, they are not at all serious.

श्री मंगल राम प्रेमी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के एक मुख्य मंत्री ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, आपने इस पर सप्लीमेंट्री नहीं करने दिया...

अध्यक्ष महोदय : प्रेमी जी, सुनिए, महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने डिस्कशन माना है, वरना मैं मानता कब था ?

Crisis in Paper Industry

*244. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the paper industry in the country is passing through a crisis because of non-availability of raw materials in adequate quantities;

(b) if so, the details of the shortage of raw materials and reasons therefor; and

(c) the measures which are being taken to resolve the problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) : The paper industry utilises a variety of raw materials such as bamboo and hardwoods, bagasse, cereal straws, waste paper etc. There is no critical shortage of these raw material at present. However, in order to sustain the existing paper mills, and to meet the future requirements of paper, it is necessary to ensure adequate availability of raw materials on a long term basis.

(c) Government are encouraging the use of secondary raw materials such as bagasse, cereal straws and waste